SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Yes, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Ahmed Patel saheb, supplementary please. ...(*Interruptions*)... अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। ...**(व्यवधान)**... बैठ जाइए, बैठ जाइए।

Bilateral trade agreements

*122. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of bilateral trade agreements that India has signed since the change of Government;

(b) the details of quantum and value of trade under each of these bilateral trade agreements in each of the past three years including the current year;

(c) the progress on talks with European Union (EU) on Free Trade Agreement (FTA/BTIA), if any; and

(d) the details of issues holding back the signing of the said agreement with EU?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OB PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government expanded the existing Free Trade Agreement (FTA) with ASEAN countries (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) to include Services and Investment. The expanded Agreement was signed in November, 2014 and came into effect from 1 July, 2015. The total trade with ASEAN countries over the last three years and the current year is given in the Statement (*See* below) to this reply.

(c) and (d) India and European Union are negotiating a Bilateral Broad Based Trade and Investment Agreement (BTIA) covering various tracks. So far fifteen rounds of negotiations have been held. Two stocktaking meetings have been held recently and both the sides have re-engaged in discussions on the India EU BTIA.

Statement

India's total trade in goods with ASEAN countries

Year	Value of Total Trade (in US $ million)
2012-13	75,874.57
2013-14	74,413.73
2014-15	76,527.35
2015-16 (April to December)	50,243.08

Note: Figures for 2015-16 (April to December) is provisional.

श्री अहमद पटेलः सर, मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में कहा है, "India and the European Union are negotiating a Bilateral Broad Based Trade and Investment Agreement covering various tracks. So far, 15 rounds of negotiations have been held."...(*Interruptions*)... मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि negotiation के जो 15 राउन्ड हुए हैं, उससे पहले क्या कोई सर्वे किया गया है? जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, उस पर इसका क्या असर होगा?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः माननीय सदस्य ने जो bilateral talks के बारे में प्रश्न पूछा है, उससे पहले और सरकार बदलने के बाद जो एग्रिमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से माननीय सदस्य को हमने लिखित रूप में बताया है। **...(व्यवधान)...**

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, has the Minister given prior intimation that the Minister of State for Parliamentary Affairs would be responding to the supplementary questions?

MR. CHAIRMAN: Yes, that information is with the Chair.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः उसके साथ ही साथ जो quantum of trade है, 2014-15, में 76,527.35 है। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)...

श्री अहमद पटेलः मैंने सर्वे के बारे में पूछा था कि डोमेस्टिक मार्केट पर क्या असर होगा? मेरा पहला सप्लीमेंट्री है, उसका तो जवाब आया नहीं। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि हम लोग एग्रिमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें जो एग्रिकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से प्रपोज़ल में उनको इम्पोर्ट किए जाने की जो बात की गई है, यह इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के बारे में सरकार क्या कुछ सोच रही है? अगर सोच रही है, तो उसकी क्या डिटेल्स हैं?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उनके पूरे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में भिजवा दूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि माननीय मंत्री जी इस समय स्वस्थ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी जो bilateral trade है ASEAN countries के साथ **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Just one minute please. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... बैठ जाए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सभी क्षेत्रों में देश की प्रगति को और देश के लोगों के सरोकार को प्राथमिकता देते हुए हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri Rangasayee Ramakrishna.

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA: Sir, most of the bilateral treaties, which were signed during the previous Government's time, have brought in an inverted duty structure, which actually militates against manufacture in India. It encourages import of the finished goods rather than raw materials and by-products. Will the Government review these agreements and correct this inverted duty structure so that the 'Make in India' programme becomes a reality?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सभापति जी, ASEAN कंट्रीज के साथ जितने भी बायलेट्रल ट्रेड एगीमेंट्स हुए हैं, सरकार समय-समय पर उनकी समीक्षा करती है। समीक्षा की दृष्टि से जिस समय भी आवश्यकता होती है, हम उस पर आगे काम करते हैं।

SHRI T. K. RANGARAJAN: Thank you, Mr. Chairman. The reply mentions about bilateral Agreement with Cambodia, Brazil, Indonesia, Laos, Malaysia, and so on. They have given four-year figures — 2012-13, 2013-14, 2014-15, and 2015-16 (up to December). Putting together, it comes to about 20,000 million dollars. I would like to know from the hon. Minister about the import figure separately for 2012-13, 2013-14, 2014-15, and for 2015-16 (up to December). How much have we exported and how much have we imported? Is India losing? More import or less export means our trade deficit increases. It is a ruination of our domestic industry and domestic products. Please give me the figures first.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है—क्योंकि जो मूल प्रश्न है, उसमें सरकार बदलने के बाद जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में पूछा गया था, माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफ़िक प्रश्न किया है, उसके उत्तर पर दृष्टि से Indian export and import to ASEAN in US million dollar, बरौनी में 2012-13 में 40 मिलियन डॉलर, 2013-14 में 32, 2014-15 में 42 और 2015-16 में 841 है। इसके अलावा और कोई भी डिटेल, जो माननीय सदस्य चाहते हैं, हम उन्हें दे देंगे।

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: He has not answered my question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Just one minute. ...(*Interruptions*)... Just one minute. ...(*Interruptions*)... The Minister has said that he will make the information available. ...(*Interruptions*)... Now, Mr. Darda ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Is it million or thousand million? ...(*Interruptions*)... Make it clear. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The Minister will make the information available. ...(*Interruptions*)... Now, Mr. Darda ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: I will give the details. ...(*Interruptions*)...

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो समस्या थी, क्या उस पर कोई समझौता हुआ है? मैं विशेष रूप से अमूल तथा अन्य जो डेयरी प्रॉडक्ट्स हैं, उनके बारे में जानना चाहता हूं कि इसको लेकर जो गतिरोध बना था, क्या वह गतिरोध दूर हो गया है? इसके साथ ही जो समझौता हुआ है, उसका प्रारूप क्या है? फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में जो गतिरोध था, इस क्षेत्र में जो दिक्कतें थी, क्या वे दूर हुई हैं? क्या उनके साथ कोई समझौता हुआ है? आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कितने राउण्ड हो चुके हैं और आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप जानते होंगे कि हमारा जो अमूल प्रॉडक्ट है, उसको अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बेचने की परमिशन है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उसको बैन किया हुआ है। इस दृष्टि से भी क्या आप इस प्रकार की कोई कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे यूरोपियन यूनियन के जो प्रॉडक्ट्स हैं, वे यहां पर न बेचे जाएं? सभापति जी, हमारे यहां की जो डेयरी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और "मेक इन इंडिया" के माध्यम से और मजबूत किया जाए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सभापति जी, यूरोपियन यूनियन के साथ इस बारे में चर्चा हुई है और अभी भी चर्चा हो रही है। जिन विषयों के बारे में माननीय दर्डा जी ने पूछा है, सरकार निश्चित तौर से उन व्यापारिक क्षेत्रों की रक्षा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: The Question Hour is not taken seriously. ...(*Interruptions*)... The Minister is unable to answer it. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please. ...(*Interruptions*)... Question No. 123.

Contract labourers under Medical Insurance Scheme

*123. SHRI TAPAN KUMAR SEN: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government has a proposal to compensate the contract labourers on retrenchment from job, if so, the details thereof; and

(b) whether Government proposes to bring the said labourers under the Medical Insurance Scheme and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.